ई संदेश

17 सितम्बर, 2026 | अंक - 223

सात दिन, सात पृष्ठ

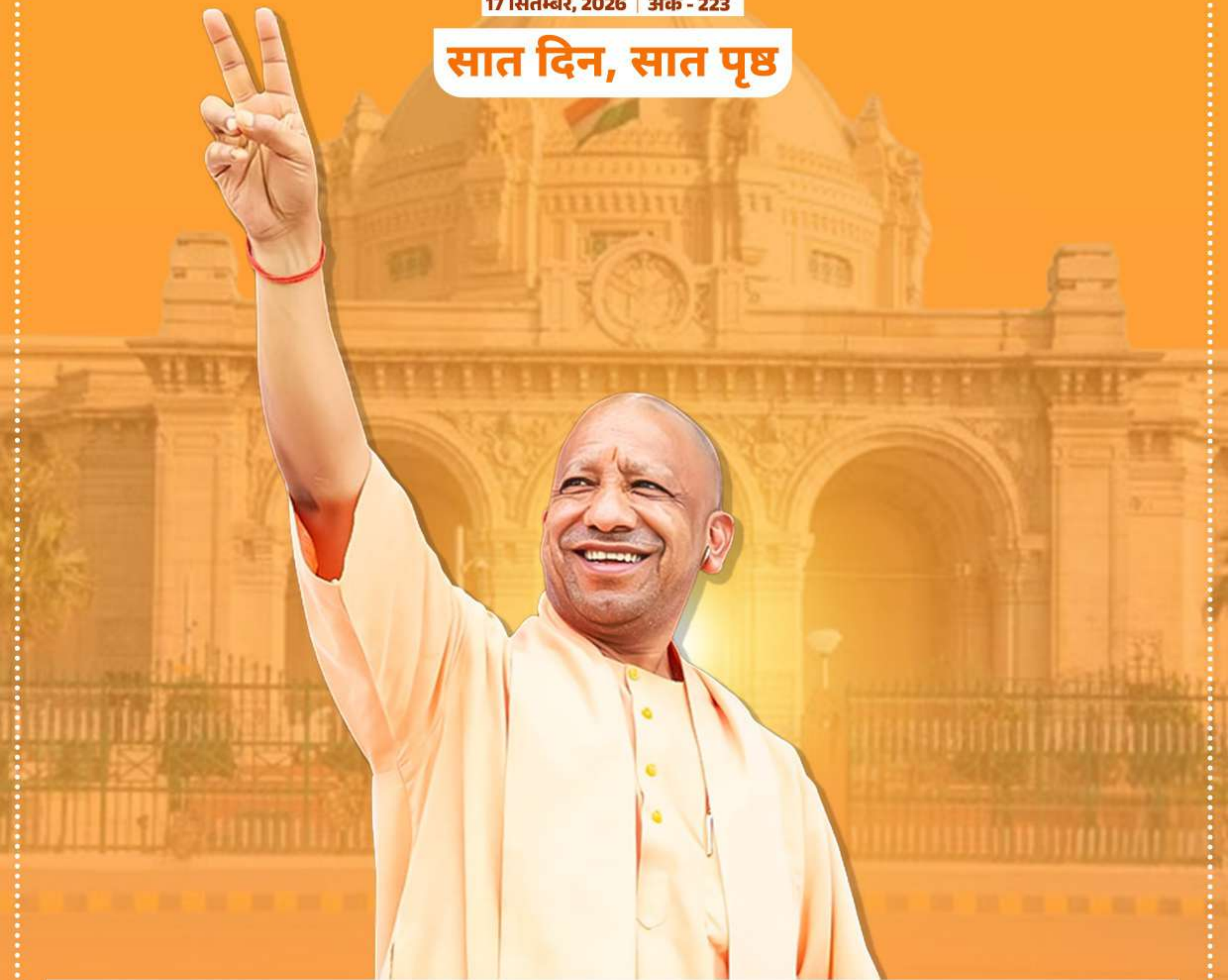

- पुस्तकों और पुस्तकालयों से होगा ज्ञान आधारित समाज का निर्माण : मुख्यमंत्री
- उपचार, शिक्षण और अनुसंधान से उत्कृष्ट संस्थान बन रहा लोहिया संस्थान : मुख्यमंत्री
- जनविश्वास ही सुशासन का आधार, संवैधानिक संस्थाएं करें मूल्यों का संरक्षण : मुख्यमंत्री
- अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना और आधुनिक न्यायिक अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
- अंतिम पायदान के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही वास्तविक सेवा : मुख्यमंत्री
- विकास, सुरक्षा और सुशासन से बदल रही उत्तर प्रदेश की तस्वीर : मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 15 सितम्बर, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

पुस्तकों और पुस्तकालयों से होगा ज्ञान आधारित समाज का निर्माण : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया द्वारा आयोजित 9 दिवसीय '05वें गोमती पुस्तक महोत्सव' (12 से 20 सितम्बर, 2026) का फीता काटकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने वन्दे मातरम् पर आधारित प्रदर्शनी एवं पुस्तक स्टॉलों का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' भेंट की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुस्तकें केवल पाठ्यक्रम तक सीमित ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज, देश और दुनिया को समझने, चिन्तन को व्यापक बनाने तथा व्यक्ति की रचनात्मकता को विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पुस्तकालय और पुस्तक संस्कृति को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में पुस्तकों और पुस्तकालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और विजन के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुस्तक महोत्सवों के माध्यम से भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस विजन को धरातल पर आगे बढ़ाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रो0 मिलिंद सुधाकर मराठे एवं निदेशक श्री युवराज मलिक का आभार जताया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ और गोरखपुर जैसे पुस्तक महोत्सवों में युवाओं की भारी सहभागिता ने उस धारणा को पूरी तरह नकार दिया है कि डिजिटल युग में युवा पुस्तकों से दूर हो रहे हैं। इस महोत्सव में स्टॉलों की संख्या 80 से बढ़कर 250 होना पुस्तक संस्कृति के विस्तार को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी नौ दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में युवाओं को ज्ञानवर्धक व रोचक पुस्तकों के साथ-साथ पुस्तक विमोचनों, लेखकों से संवाद और महापुरुषों की जीवन गाथाओं को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि केवल शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ने से कोई पूर्ण ज्ञानवान नहीं हो सकता। सफलता की अपनी एक यात्रा होती है, जिसमें ठोकरों और असफलताओं के बावजूद हार न मानने वाला व्यक्ति ही मंजिल तक पहुंचता है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' प्रत्येक बच्चे, युवा और नागरिक के लिए सम्बल और मार्गदर्शक है। जीवन की विभिन्न परीक्षाओं और कठिन परिस्थितियों में जब व्यक्ति का हौसला डगमगाने लगता है, तब यह पुस्तक सकारात्मक दिशा दिखाती है। इसलिए प्रत्येक युवा को इसे पढ़कर इसके संदेशों को आत्मसात करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' के उद्घोष के साथ सदैव सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचारों के स्वागत की प्रेरणा देती रही है। श्रुति, स्मृति, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों से समृद्ध इस परम्परा का केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। लखनऊ की साहित्यिक परम्परा, नैमिषारण्य के 88 हजार ऋषियों की ज्ञानधारा, काशी के प्राचीन विश्वविद्यालय, प्रयागराज कुम्भ की वैचारिक स्थली और मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम वाचन की परम्परा राज्य के गौरवशाली अतीत का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब इस ज्ञान परम्परा और विरासत से दूरी बनाई गई, तो उत्तर प्रदेश को 'बीमारू राज्य' की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया और युवाओं के समक्ष पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। विगत वर्षों के सकारात्मक प्रयासों से यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और डिजिटल युग ने शहर व गांव की दूरी समाप्त कर युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सभी 57,600 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की व्यवस्था विकसित की है। प्रत्येक ग्राम सचिवालय में नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय एवं डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, जहां बैठकर ग्रामीण युवा अध्ययन कर रहे हैं और ग्राम्य जीवन को समझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में सुधार कर स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। चित्रकूट जैसे आकांक्षी जनपद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सुविधाएं मिलने पर तीसरी कक्षा की छात्रा ने स्वयं डिजिटल लाइब्रेरी संचालित कर अपनी क्षमता दिखाई। उन्होंने बताया कि 'निपुण भारत' के माध्यम से बच्चों में बुनियादी भाषा व अंक ज्ञान का विकास हुआ है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले की अपेक्षा आज विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित कई बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, जिनका सदुपयोग जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अपनी रुचि का साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, वैज्ञानिकों के शोध अथवा महापुरुषों की आत्मकथाएं पढ़कर अपना व्यक्तिगत 'बुक बैंक' बनाएं। खाली समय में पुस्तकों का अध्ययन युवाओं की रचनात्मकता को निखारने का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पुस्तक मेले युवाओं को अपनी राह स्वयं तैयार करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं। युवा यहां प्रकाशकों की विविधता और रचनात्मक साहित्य को गहराई से समझें। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, नेशनल बुक ट्रस्ट और सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन को और विस्तार दिया जाएगा तथा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे पुस्तक महोत्सव आयोजित होंगे, जिनमें राज्य सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों की व्यापक स्तर पर खरीद कर रही है, ताकि गांवों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक ज्ञानवर्धक पुस्तकें सुलभ हों। उन्होंने युवाओं से महोत्सव से कम से कम एक रचनात्मक पुस्तक खरीदने, उसका अध्ययन करने और अपने अनुभव साझा करने की अपील की।

उपचार, शिक्षण और अनुसंधान से उत्कृष्ट संस्थान बन रहा लोहिया संस्थान : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 13 सितम्बर, 2026 को लखनऊ स्थित डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के षष्ठम स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में इस संस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले अधिकांश मरीजों की पहली पहुँच यहीं होती है। पहले बड़ी संख्या में डायलिसिस के मरीज यहाँ आते थे, जबकि आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 10-10 बेड की निःशुल्क डायलिसिस सुविधा सुलभ करायी जा चुकी है। मात्र छह वर्ष की संक्षिप्त अवधि में संस्थान द्वारा अर्जित प्रगति अत्यंत प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने संस्थान में 40 बेड युक्त इमरजेंसी मेडिसिन वॉर्ड, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 100 मरीजों हेतु वेटिंग हॉल, मुख्य चिकित्सा भवन में अंग प्रत्यारोपण यूनिट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में 4-डी सी0टी0 सिमुलेटर मशीन, 1.5 टेस्ला एम0आर0आई0 मशीन, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के अंतर्गत स्पेक्ट सी0टी0 मशीन, पी0एम0आर0 विभाग में नेविगेटेड आर0टी0एम0एस0 मशीन तथा इण्डोब्रोन्कियल अल्ट्रासाउण्ड मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने विभिन्न तकनीकी पदों पर नवचयनित 194 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए, उत्कृष्ट कार्य करने वाले संकाय सदस्यों को सम्मानित किया और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 में इस अस्पताल को संस्थान के रूप में उच्चीकृत करने का दृढ़ निर्णय लिया गया था। कभी 20 बेड के प्राथमिक स्वरूप से शुरू हुआ यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त संसाधनों एवं समर्पित फैकल्टी के सहयोग से आज 1,400 बेड के सुपर स्पेशियलिटी संस्थान का रूप ले चुका है। इसकेसाथ ही परिसर में 1,000 बेड का नया अस्पताल और 300 बेड का आधुनिक ट्रॉमा सेण्टर भी आकार ले रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हीलिंग, लर्निंग और डिस्कवरी का समन्वय ही किसी भी चिकित्सा संस्थान को 'सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस' बनाता है। यहाँ उपचार, शिक्षण और अनुसंधान तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने चिकित्सकों को मरीज-केन्द्रित अनुभव व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और शोध पत्र लिखने की आदत डालने के निर्देश दिए, जिससे भावी अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा मिल सके। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि संस्थान की कार्यप्रणाली में सुधार से जनशिकायतों में भारी कमी आई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुचिता का सीधा प्रभाव संस्थान की साख पर पड़ता है। पारदर्शी नीति के चलते विगत नौ वर्षों में प्रदेश में नौ लाख युवाओं को पूर्ण निष्पक्षता से सरकारी सेवा में अवसर दिया गया है। इसी सुशासन का परिणाम है कि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना वृद्धि हुई है तथा उत्तर प्रदेश के नागरिकों के समक्ष अब पहचान का कोई संकट नहीं है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लाण्ट यूनिट का लोकार्पण हो चुका है और शीघ्र ही बोन मैरो ट्रांसप्लाण्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। किडनी ट्रांसप्लाण्ट के क्षेत्र में संस्थान की क्षमता का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना', 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' और 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा' के साथ-साथ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से निर्धनों के उपचार हेतु पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की गई है। अब वास्तविक चुनौती प्रतीक्षा सूची को न्यूनतम करने की है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, गामा नाइफ, ए0आई0-आधारित डायग्नोस्टिक, उन्नत इमेजिंग और डिजिटल हेल्थ की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। संस्थान द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों में वर्चुअल आई0सी0यू0 संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को टेली-कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन का व्यापक विस्तार करने के निर्देश दिए, ताकि तृतीयक चिकित्सा संस्थानों में अनावश्यक भीड़ कम हो सके और गम्भीर रोगियों पर पूरा ध्यान दिया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में मात्र 41 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 85 हो चुके हैं। प्रदेश में गोरखपुर व रायबरेली में दो एम्स सफलतापूर्वक संचालित हैं। एम0बी0बी0एस0 की सीटें 4,690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हो चुकी हैं। नर्सिंग कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर 26 हो गई है तथा 33 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की संख्या 1,027 से बढ़कर 3,438 तक पहुँच चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के बुनियादी विकास हेतु पूँजीगत व्यय की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चिकित्सा जगत से पारम्परिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय पर बल दिया। उन्होंने सचेत किया कि क्लिनिकल डेटा का वैज्ञानिक संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारे शोध का लाभ देश को मिले। उन्होंने कोविड काल में मात्र नौ माह में दो स्वदेशी टीके तैयार करने और 100 मित्र देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के भारत के सामर्थ्य का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार आई 0 आई0टी0 कानपुर और एस0 जी0 पी0जी 0आई0 के साथ मिलकर मेडटेक के सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर रही है। प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का तीव्र विकास हो रहा है। देश का सबसे बड़ा फार्मा बाजार होने के नाते अब प्रदेश में दवा निर्माण और शोध को नई गति दी जा रही है। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को आई0आई0टी0 और आई0आई0एम0 जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ तालमेल बिठाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए0आई0) का अधिकाधिक उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि समय से आगे की सोच और नवाचार ही भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का आधार हैं। कोविड प्रबंधन में ग्राउंड लेवल पर दस्तक अभियान, टेस्टिंग व फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की सक्रियता का स्मरण कराते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पष्ट विजन और पर्याप्त संसाधनों के समन्वय से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोहिया संस्थान आने वाले समय में क्लीनिकल, अकादमिक एवं रिसर्च एक्सीलेंस के एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा।

जनविश्वास ही सुशासन का आधार, संवैधानिक संस्थाएं करें मूल्यों का संरक्षण : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को लखनऊ में लोकायुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश के 50वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत किसी भी संवैधानिक संस्था में सामान्य नागरिक का अटूट विश्वास है। गुड गवर्नेंस पूरी तरह पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है और यदि जनता का भरोसा नहीं है, तो सुशासन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुशासन की वास्तविक कसौटी यही है कि समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी संवैधानिक संस्थाओं पर गर्व की अनुभूति हो तथा उसकी समस्याओं का समयबद्ध व नियमानुसार समाधान सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लोकायुक्त प्रशासन की स्मारिका एवं सूचना पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि किसी लोक सेवक द्वारा गलत कार्य किए जाने और उसे बचाने के प्रयासों की स्थिति में लोकायुक्त संगठन मेरिट के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करता है। 'प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति और पद मिलने पर उच्छृंखल व्यवहार को रोकने तथा पद के साथ मर्यादा एवं नैतिकता का अनुपालन कराने के लिए ऐसा प्रभावी संस्थागत अंकुश अपरिहार्य है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1975 की आपातकालीन परिस्थितियों के उपरांत बनी सरकार के प्रयासों से 14 सितम्बर, 1977 को न्यायमूर्ति विशम्भर दयाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन का गठन हुआ था। आज 50 वर्षों की यह यात्रा एक परिपक्व पड़ाव पर पहुंच चुकी है और वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा के नेतृत्व में यह संगठन नई आभा के साथ कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि लोकायुक्त संगठन की विगत 50 वर्षों की यात्रा का व्यापक डॉक्युमेंटेशन तैयार किया जाए, जिसमें अब तक प्राप्त मामलों, उनके निस्तारण और की गई कार्रवाइयों का संपूर्ण विवरण संकलित हो। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती केवल अतीत के सिंहावलोकन तक सीमित न रहे, बल्कि संगठन को आगामी 50 वर्षों की सुदृढ़ कार्ययोजना और रोडमैप भी तैयार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के लोकपाल तथा देशभर के लोकायुक्तों को आमंत्रित कर एक वृहद सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें विभिन्न राज्यों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) पर सार्थक संवाद हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि संगठन की कार्यपद्धति को अधिक पारदर्शी, स्वच्छ, नैतिक और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सकारात्मक सहयोग निरंतर उपलब्ध कराती रहेगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि संविधान निर्माताओं ने न्याय, सत्य और समता को व्यवस्था की आधारशिला माना है। न्याय जाति, मत या संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि केवल शिकायत की मेरिट और सत्य की कसौटी पर होना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और ई-गवर्नेंस जैसी तकनीकें प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाएंगी। साथ ही उन्होंने सचेत किया कि शिकायत निवारण तंत्र का दुरुपयोग न हो, क्योंकि बिना ठोस आधार के की गई अनावश्यक शिकायतें ईमानदार नागरिकों के न्याय में बाधा बनती हैं।

प्रशासन में तकनीक के सफल प्रयोग का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में जनता दर्शन में आने वाली 60 प्रतिशत शिकायतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़ी होती थीं। सरकार ने 80 हजार उचित दर दुकानों को ई-पॉस मशीनों से जोड़ा और खाद्यान्न ट्रकों की ट्रैकिंग सुनिश्चित की, जिससे आज यह शिकायतें शून्य हो चुकी हैं और 16 करोड़ लोगों को पूरी पारदर्शिता के साथ राशन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 में राजस्व विभाग में भूमि विवाद, पैमाइश, वरासत और नामान्तरण के करीब 34 लाख मामले लंबित थे। समय-सीमा तय कर विगत नौ वर्षों में इन सभी 34 लाख लंबित मामलों का निस्तारण कराया गया है तथा नए मामलों की मेरिट आधारित जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमि पैमाइश में मानवीय भूल रोकने के लिए अब पारंपरिक जरीब के स्थान पर तहसीलों में आधुनिक रोबोटिक तकनीक और डिजिटल को-ऑर्डिनेट प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे इंच स्तर तक सटीक पैमाइश हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डीबीटी प्रणाली ने बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त कर जनता का विश्वास सुदृढ़ किया है। वर्तमान में प्रदेश के 1.10 करोड़ पेंशनरों को 12 हजार रुपये वार्षिक पेंशन बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।

समारोह में लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने कहा कि संगठन की 50 वर्षों की यात्रा विश्वसनीयता, निष्पक्षता और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का प्रतीक है। उपलोकायुक्त सुरेन्द्र कुमार यादव, उपलोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह तथा उपलोकायुक्त शम्भू सिंह यादव ने भी विचार व्यक्त करते हुए बताया कि संगठन में वर्ष 2017 से 2025 के बीच परिवादों के निस्तारण की औसत दर लगभग 90 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 98 प्रतिशत रही है।

अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना और आधुनिक न्यायिक अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को जनपद प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बार काउन्सिल और बार एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस कल्याणकारी योजना को लागू किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफिस चेम्बर और अधिवक्ता भवन की चाभी सौंपी। 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं की क्षमता वाले इस आधुनिक परिसर में बहुस्तरीय पार्किंग, भोजन कक्ष, पुस्तकालय व सामुदायिक कक्ष की सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस, हरितालिका तीज एवं गणेश चतुर्थी की बधाई देते हुए प्रयागराज की पावन ज्ञान व न्याय की धरती को नमन किया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से 400 अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें शासन व न्यायालय के प्रकरणों की अद्यतन जानकारी प्रभावी ढंग से मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन की ओर से चैम्बरों में फर्नीचर व उपकरणों से संबंधित न्यायपालिका अथवा मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से आने वाले प्रत्येक प्रस्ताव पर राज्य सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिवक्ता समाज देश के प्रबुद्ध वर्ग का अभिन्न अंग है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। प्रयागराज की धरती ने पं0 मोतीलाल नेहरू, महामना पं0 मदन मोहन मालवीय तथा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जैसी विभूतियों की स्मृतियों से देश के विधिक व संवैधानिक विमर्श को नई दिशा दी है। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के योगदान के सम्मान में ही सरकार ने प्रयागराज में 'डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय' की स्थापना की है, जिसका भव्य परिसर निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि न्याय का रथ बार और बेंच रूपी दो पहियों पर गतिशील रहता है और दोनों के बीच निरंतर संवाद, समन्वय व परस्पर सम्मान सुशासन की पहली शर्त है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में पुलिस बल में 45 से 50 प्रतिशत पद रिक्त थे और न्यायिक अवसंरचना जर्जर थी। वर्तमान सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण क्षमता को 3 हजार से बढ़ाकर 60 हजार वार्षिक किया और पुलिस व अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गवाहों को निर्भीक बनाने के लिए राज्य में प्रभावी गवाह संरक्षण व्यवस्था लागू की गई है तथा कैदियों की पेशी के लिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए गए हैं। न्यायालयों और कारागारों को हाई-स्पीड इंटरनेट तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर वर्चुअल गवाही और मुकदमों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन अभियोजन और वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए दोषसिद्धि दर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किराए के भवनों में चल रहे 10 जिला न्यायालयों के लिए एकीकृत न्यायालय परिसर (इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स) का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इन परिसरों में न्यायिक अधिकारियों के आवास, अधिवक्ताओं के चैम्बर, खेल सुविधाएं, इनडोर स्टेडियम और सस्ती कैंटीन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। त्वरित न्याय के लिए प्रदेश में प्रथम चरण में 900 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि की सहायता राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तथा अधिवक्ता के निधन पर मिलने वाली आर्थिक सहायता की पात्रता आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष की है। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी, लखनऊ, कासगंज, श्रावस्ती सहित लगभग एक दर्जन जिलों में अधिवक्ता चैम्बरों का निर्माण कराया जा रहा है तथा राज्य विधि अधिकारियों की फीस में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू तीन नए कानूनों—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय न्याय संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के क्रियान्वयन में अधिवक्ता समाज का सहयोग सराहनीय रहा है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं का आह्वान किया कि वे साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, फिनटेक और पर्यावरण जैसे नवीन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर संवैधानिक मूल्यों के सजग प्रहरी बनें।

समारोह को सम्बोधित करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने अधिवक्ताओं हेतु आधुनिक कक्षों व पार्किंग के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

अंतिम पायदान के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही वास्तविक सेवा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 सितम्बर, 2026 को गोरखपुर में इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आई0एम0ए0) चैरिटेबल ब्लड सेण्टर का लोकार्पण करते हुए कहा कि किसी भी संस्था की वास्तविक पहचान इस बात से तय होती है कि उसने अपनी विशेषज्ञता का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में क्या योगदान दिया है। उन्होंने पेशेवर दायित्वों से आगे बढ़कर चैरिटेबल ब्लड बैंक और निःशुल्क ओ0पी0डी0 संचालित करने के लिए आई0एम0ए0 की सराहना की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई0एम0ए0 केवल चिकित्सकों का व्यावसायिक संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्था है। वर्ष 2017-18 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर आधुनिक ब्लड बैंक की स्थापना कर संगठन ने 'जहां चाह, वहीं राह' की उक्ति को चरितार्थ किया है। यह केंद्र चैरिटी के माध्यम से जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि तकनीक और उत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जुटाए जा सकते हैं, किंतु रक्त का निर्माण संभव नहीं है। चिकित्सक अपनी मानवीय संवेदना से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेटर यूनिट स्थापित करने पर बल दिया, जिससे डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मांग पूरी हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मांग के अनुरूप रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक अपीलों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान को जनांदोलन बनाएं। साथ ही, उन्होंने गंभीर बीमारियों से ग्रसित पेशेवर रक्तदाताओं पर सख्त अंकुश लगाने के निर्देश दिए, ताकि संक्रमण के बड़े संकट से बचा जा सके। ऐसे मामलों को शासन-प्रशासन के संज्ञान में लाने का आह्वान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि वाराणसी, बरेली और प्रयागराज के बाद अब गोरखपुर में भी आई0एम0ए0 ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। गोरखपुर शाखा के 1,400 से अधिक सदस्य जनसेवा में समर्पित हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के ऐतिहासिक विकास को रेखांकित करते हुए उन्होंने गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ की गई डायलिसिस यूनिट और आईसीयू सेवाओं का भी स्मरण किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 8-9 वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। कभी बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज संसाधनों के अभाव और एक बेड पर चार-चार मरीजों के दबाव से जूझता था और क्षेत्र में इन्सेफेलाइटिस का भय व्याप्त था। आज वही संस्थान सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं से युक्त होकर उपचार का प्रमुख केंद्र बन चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' की नीति से प्रदेश में 85 मेडिकल कॉलेज और दो एम्स संचालित हो रहे हैं। गोरखपुर में एम्स, दो मेडिकल कॉलेज और चार विश्वविद्यालय सक्रिय हैं, जबकि कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज सहित आसपास के जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ हो चुके हैं। प्रत्येक जिला अस्पताल में 10-10 बेड पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की सीटें 4,600 से बढ़कर 13,500 से अधिक हो चुकी हैं तथा पी0जी0 की सीटें दोगुनी हो गई हैं। नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। चिकित्सा शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई0आई0टी0 कानपुर के साथ मेडिटेक सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस और एस0जी0पी0जी0आई0 में भी एक्सीलेंस सेण्टर विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संगठित माफिया तंत्र की समाप्ति के बाद अब प्रदेश के चिकित्सक, व्यापारी और आम नागरिक पूरी तरह सुरक्षित वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जो नए उत्तर प्रदेश और सशक्त गोरखपुर के नव-निर्माण का स्पष्ट प्रमाण है।

विकास, सुरक्षा और सुशासन से बदल रही उत्तर प्रदेश की तस्वीर : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 16 सितम्बर, 2026 को गोरखपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत वाली 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और समग्र विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने उर्वरक नगर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नवनिर्मित कल्याण मण्डपम् (कन्वेंशन सेण्टर) का लोकार्पण व अवलोकन किया तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसकी लाभार्थी संख्या और धनराशि में शीघ्र ही और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 07 अक्टूबर, 2026 से एक सप्ताह तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत वंचित पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के तहत टी0जी0टी0, पी0जी0टी0 और बेसिक शिक्षा परिषद के शहरी क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगामी छह माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बताया कि 19 सितम्बर से पुलिस एवं होमगार्ड के लगभग 77 हजार पदों पर वृहद भर्ती अभियान शुरू होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर महानगर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 09 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए थे जहां महंगे बारात घर उपलब्ध नहीं थे। विधायक निधि, नगर निगम और जीडीए के सहयोग से मानबेला, बिछिया, जंगल बेनी माधव और बसारतपुर में पहले ही कल्याण मण्डपम जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। आज उर्वरक नगर में लोकार्पण के उपरांत तथा झारखण्डी व सेमरा में निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होते ही महानगर में कुल 10 कल्याण मण्डपम उपलब्ध हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था स्थापित कर भयमुक्त वातावरण बनाया गया है। चौड़ी सड़कों, फोर-लेन कनेक्टिविटी, नकहा पुल, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवरों से आवागमन सुगम हुआ है। बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने को पुनः चालू करने, स्पोर्ट्स कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार और फर्टिलाइजर परिसर में सैनिक स्कूल की स्थापना से नई पहचान स्थापित हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चार दशकों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मासूमों की जान लेने वाली इन्सेफेलाइटिस जैसी महामारी पर सरकार ने प्रभावी रणनीतियों से मात्र दो वर्ष में पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। वर्तमान में गोरखपुर एम्स, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज जैसी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और रामगढ़ताल के कायाकल्प से पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार निःशुल्क खाद्यान्न, आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को संबल दे रही है। वर्ष 2017 के बाद से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुका है। गीडा सहित गोरखपुर में 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे लगभग 50 हजार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से विकास, सुशासन और सुरक्षा के संकल्प के साथ एकजुट होकर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनने की अपील की।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 15 सितम्बर, 2026 को नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौता के अवसर पर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 15 सितम्बर, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 500 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसके क्रियान्वयन से 30 दिन की उपस्थिति पर भत्ते में प्रतिमाह 3,000 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 'मुख्यमंत्री पी0आर0डी0 कैशलेस चिकित्सा योजना' के माध्यम से प्रति परिवार प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये की सीमा तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। योजना में संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

- मंत्रिपरिषद ने प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड 6-लेन चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे का 15.172 कि0मी0 लम्बाई में ई0पी0सी0 मोड पर विकास किए जाने हेतु पूँजीगत मदों के लिए 1008.67 करोड़ रुपये की मूल्यांकित लागत को अनुमोदित किया है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा किया जाएगा।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अभियंत्रण विभागों (यथा- लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण आदि) में कार्यों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन हेतु अभियन्ताओं को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के कस्बा शोहरतगढ़ व बढ़नी तथा जनपद हरदोई की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन निर्माण हेतु राजस्व विभाग की चिन्हित भूमि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उपयोगार्थ परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित एवं नामान्तरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए0टी0एस0) की मान्यता, विनियमन व नियंत्रण के सम्बन्ध में 'नवीन राज्य नीति, 2026' निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- मंत्रिपरिषद ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 14,429 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएंगी।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन छाता शुगर कम्पनी लि0, जनपद मथुरा की लगभग 20 एकड़ भूमि पर 'कन्सेशन-कम-लीज' व्यवस्था पर निजी निवेश के माध्यम से ग्रेन/शीरा (डुअल मोड) आधारित न्यूनतम 120 के0एल0पी0डी0 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने पूर्वांचल क्षेत्र (गोरखपुर) में 'वर्ल्डफिश उ0प्र0 फिशरीज प्रोजेक्ट सेण्टर योजना' के संचालन हेतु मत्स्य विभाग एवं वर्ल्ड फिश के मध्य समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है।

- मंत्रिपरिषद ने 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के अन्तर्गत उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा लघु व सीमान्त कृषकों को 06 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण 6 प्रतिशत रियायती वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने तथा ब्याज अनुदान व शाखाओं के आधुनिकीकरण हेतु 384 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष 25 रुपये प्रति कुन्तल की दर से अतिरिक्त मार्जिन (लाभांश) राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

- मंत्रिपरिषद ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' (एन0एस0जी0) के 'रीजनल हब' की स्थापना हेतु जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम पूरे लालखां की 26.000 हेक्टेयर (लगभग 65 एकड़) बंजर भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

- मंत्रिपरिषद ने 10 वर्ष तक की अवधि के 10 लाख रुपये से अधिक के पंजीकृत किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर भी 10 लाख रुपये तक की सीमा तक स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट के विस्तार सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई0सी0एच0एस0) के अन्तर्गत 13 जनपदों में पॉलीक्लीनिक निर्माण हेतु स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एल0एम0ए0), भारत सरकार को ग्राम पंचायत/स्थानीय निकायों की भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जेल वॉर्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को (04 वर्ष की सेवा उपरान्त) अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट के साथ 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

- मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 और बाद के वर्षों में सेवा से बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पद की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट के साथ 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (ए0पी0आई0एल0) की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूर्ण कराने हेतु एन0सी0एल0टी0 के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा टेकओवर का पक्ष रखने तथा अनुषांगिक कार्यवाही हेतु अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- मंत्रिपरिषद ने 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज तथा रायबरेली विकास प्राधिकरणों की परियोजनाओं हेतु 655.76 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में कुल 380 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति व धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित